एनआईटी में सरकारी जमीन पर प्राइवेट अस्पताल...

पेज एक का शेष

जगह सोसायटी को दे दी। इस संबंध में एमसीएफ ने जो लीगल राय ली थी, उसमें कहा गया था कि वह स्थायी रूप से इस जगह को धर्मार्थ अस्पताल के लिए नहीं दे सकती। बीच में जब एमसीएफ ने जमीन वापस लेनी चाही तो सोसायटी ने इस पर स्टे भी हासिल कर लिया लेकिन अब वह स्टे भी हट चुका है। यानी एमसीएफ जब चाहे इस जमीन को ले सकता है लेकिन सत्ता और विपक्षी दलों के नेताओं ने एमसीएफ के हाथ बांधे हुए हैं।

बंट गई पंजाबी बिरादरी, लग गया ताला

रोशन लाल गेरा के बाद 2017 में श्रीरामजी चैरिटेबल अस्पताल सोसायटी के अध्यक्ष कंवल खत्री बनाए गए। खत्री ने जब चार्ज संभाला तो सोसायटी पर 23 लाख का कर्ज था। उन्होंने धीरे-धीरे तमाम एनजीओ की मदद लेकर अस्पताल के हालात संभालने की कोशिशें शुरू कर दीं। लेकिन उनके ऊपर आरोप लगा कि खुद को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को सोसायटी का सदस्य बना दिया। सोसायटी में बृजमोहन भाटिया के परिवार से जितेन्द्र कुमार भाटिया महासचिव और विशाल भाटिया उपप्रधान थे। लेकिन सोसायटी पर कब्जा जमाने के चक्कर में भाटिया ग्रुप नजरन्दाज हो रहा था।

इस दौरान मामले को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों की सहमति से समाजसेवी और भाजपा नेता आनंदकांत भाटिया इसके समझौता अधिकारी (आर्बिट्रेटर) भी बने। लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद महासचिव और उपप्रधान ने कंवल खत्री से सोसायटी के सभी लेन-देन कैशलेस करने को कहा लेकिन कंवल खत्री ने कहा कि छोटे कर्मचारियों को पैसे देने के लिए कैशलेस से दिक्कत आएगी। बीच में आनंदकांत भाटिया ने ऐसे कर्मचारियों के खाते बैंक में सोसायटी की ओर से खुलवाने की पेशकश की। लेकिन बात बनी नहीं। दोनों गुटों की खाई बढ़ती गई।

इसी बीच सोसायटी के सदस्यों की आम राय से एक प्रस्ताव पास कर कंवल खत्री को उनके प्रधान पद से 23 अगस्त 2019 को हटा दिया गया। उसी दौरान कंवल खत्री गुट ने 1 सितम्बर 2019 को सोसायटी की एजीएम बुला रखी थी। उन्हें भाटिया गुट ने चेतावनी दी कि वे एजीएम बुलाने की हिमाकत न करें। यह रस्साकशी 2019 से चलती हुई 2020 तक आ पहुंची और फरवरी 2020 में सोसायटी के धर्मार्थ अस्पताल पर ताला लग गया। इसी दौरान कोराना ने पैर पसारना शुरू कर दिया और सभी गुट घरों में बैठ गए। इस दौरान इस मामले में रजिस्ट्रार सोसायटीज के जिला फरीदाबाद दफ्तर और चंडीगढ़ स्थित प्रदेश के दफ्तर से अलग-अलग आदेश हासिल किए गए। रजिस्ट्रार सोसायटीज ऐसी हरकतों और बदमाशियों के लिए पहले से ही बदनाम है।

इन्ही झगड़ों के बीच जिला रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटीज ने 8 मार्च को रिटायर कर्नल संत पाल को सोसायटी का प्रशासक नियुक्त कर दिया। उनका भत्ता भी 21000 रुपये प्रति माह तय कर दिया गया। प्रशासक संत पाल अस्पताल की चाबी मांगने कभी कंवल खत्री के पास तो कभी जितेन्द्र कुमार भाटिया के पास आए। लेकिन अस्पताल की मुख्य चाबी पीर जगन्नाथ के पास है। हालांकि रजिस्ट्रार सोसायटीज इस मामले को सुलझाने की बजाय और तूल दे रहा है। वह चाहे तो तीन दिन में दोनों पक्षों की बैठक बुलाकर मामले को सुलझा सकता है लेकिन वह ऐसा कर नहीं रहा है। उसने जिस तरह यहां प्रशासक बैठाया है और उसका वेतन तय कर दिया है, इसी से उसकी मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। जब तक रजिस्ट्रार का कोई फैसला नहीं आता, तब तक धर्मार्थ अस्पताल पर ताला लगा रहेगा। इस तरह एमसीएफ अपनी जमीन भी सोसायटी से वापस नहीं ले सकेगा।

पीर जगन्नाथ की भूमिका

फरीदाबाद की पंजाबी बिरादरी में पीर जगन्नाथ की काफी चलती है। धार्मिक व्यक्ति होने की वजह से लोग उनकी बात मानते हैं।

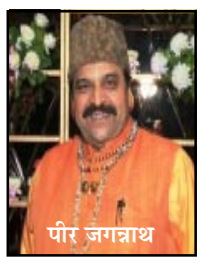

फरीदाबाद एनआईटी क्षेत्र से जो भी विधायक जिस भी पार्टी का बनता है, वह भी पीर जगन्नाथ के हिसाब से ही चलता है। फरीदाबाद की पंजाबी बिरादरी के लोगों का कहना है कि पीर जगन्नाथ इस मामले में फैसला उस शख्स के हक में करेंगे यानी अस्पताल की चाबी उसको सौपेंगे, जो उनकी नजर में सही होगा। लेकिन उससे पहले दोनों ही पक्षों को रजिस्ट्रार सोसायटीज के यहां से अपनी-अपनी संगीन शिकायतों को वापस लेना होगा। रजिस्ट्रार के यहां जब तक दोनों पक्ष बने रहेंगे, तब तक पीर जगन्नाथ के फैसले का कोई महत्व नहीं है। इस तरह पंजाबी बिरादरी दो फाड़ हो गई है। शहर के कुछ प्रतिष्ठित लोग कंवल खत्री के साथ तो कुछ प्रभावशाली लोग जितेन्द्र कुमार भाटिया और विशाल भाटिया के साथ हैं। बिरादरी के लोग तभी एक होंगे जब पीर जगन्नाथ अपना फैसला सुनाएंगे।

पंजाबी बिरादरी का कहना है कि धर्मार्थ अस्पताल की जमीन को लेकर हमें कोई चिन्ता नहीं है। पहले कांग्रेस हमारी मदद करती थी, अब भाजपा हमारी मदद करती है। विधायक सीमा त्रिखा ने अस्पताल के लिए 11 लाख रुपये दिए। आनंदकांत भाटिया भी गरीबों के लिए इस अस्पताल को दोबारा से चलता हुआ देखना चाहते हैं। उनके प्रयास इस दिशा में अलग तरह से हैं। इसलिए एमसीएफ तो इस बात को भूल जाए कि ये जमीन उसे वापस मिलेगी। एमसीएफ को जमीन वापस लेने के लिए भाजपा की सरकार से एनओसी लेनी होगी। सरकार कहकर तो देखे कि धर्मार्थ अस्पताल को बंद कर जमीन एमसीएफ को दी जाए। यहां कोई गलत काम नहीं हो रहा है बल्कि जमीन अगर एमसीएफ को वापस गई तो वहां के अधिकारी इसे बेच खाएंगे।

खट्टर ने पुलिस को सौंपा परिवहन विभाग....

पेज एक का शेष

पीड़ित सामने आने की गुस्ताखी नहीं कर सकता क्योंकि उनका विश्वास है कि यह सारा खेल राजनेताओं की मिलीभगत एवं साझेदारी में हो रहा है; इसलिये लुटेरों का तो बिगड़ना कुछ नहीं और सामने आने वाले का बचेगा कुछ नहीं। पीड़ित बताते हैं कि लूट का सिलसिला व्यवसायिक वाहन खरीदने से ही शुरू हो जाता है। ज्यों ही कोई नया वाहन खरीदा जाता है उसकी फ़िटनेस जांच के नाम पर 800 रुपये सरकारी फ़ीस तथा 2700 रुपये की रिश्वत वसूली जाती है। यह पासिंग हर दो साल बाद इसी तरह से होती है। इसके बाद गाड़ी के रजिस्ट्रेशन व अन्य दस्तावेज़ बनते हैं जिसके लिये सरकारी फ़ीस के ऊपर 7000 रुपये वसूले जाते हैं। इन दोनों बड़े शहरों में 10-10 हजार के करीब नई गाड़ियां प्रति वर्ष आती हैं। नेशनल परमिट की फ़ीस 17500 के अलावा 1000 रुपये की रिश्वत अलग से लगती है।

किसी इक्का-दुक्का गाड़ी को छोड़ कर तमाम गाड़ियां बैंक में गिरवी रख कर कर्ज पर खरीदी जाती हैं। इस तथ्य का इन्दराज वाहन के रजिस्ट्रेशन पर किया जाता है। कर्ज पूरा हो जाने पर इस इन्दराज को उतरवाने की रिश्वत 1000 रु. तथा सरकारी फ़ीस 500 है। समझने वाली बात यह है कि जब साल भर में करीब दस हजार वाहन दर्ज होंगे तो उन सभी वाहनों के उक्त सभी काम भी यहीं होंगे। अब जोड़ते रहिये हिसाब कि उक्त दरों से सालाना अथवा मासिक कितनी लूट-कमाई इन दफ़्तरों में नियंतिम रूप से होती है। उक्त मोटे काम के अलावा छोटा काम तिमाही रोड टैक्स भरने का है। टैक्स तो 2400 या कुछ भी वाहन के अनुसार हो सकता है परन्तु रिश्वत 150 रु. फिक्स है। यह रकम छोटी जरूर है परन्तु हर वाहन साल में चार बार इसे अदा करता है तो कुल रकम कितनी होगी समझना कठिन नहीं। एक और बड़ा काम है एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाणपत्र। जब कोई वाहन किसी अन्य क्षेत्र में बिकता है तो रजिस्ट्रेशन कार्यालय से यह एनओसी लेना पड़ता है। इसकी सरकारी फ़ीस तो मात्र 150 रु. रखी गयी है लेकिन जब तक 5000 रु. ऊपर से न दिये जायें तो यह एनओसी नहीं मिलता और इसको लिये बिना लाखों रुपये की (वाहन) डील सम्पन्न नहीं हो पाती।

उक्त कारोबार के अलावा नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना तथा पुराने का नवीकरण कराना भी अपने आप में एक बड़ा धंधा है। पहले, इसकी कोई सही व्यवस्था न होने के चलते लोग यूपी, बिहार व बंगाल आदि से असली-नकली लाइसेंस बनवा कर लाते थे, फ़िर फ़र्जीवाड़े के जरिये यहां नवीकरण कराते थे। लेकिन बीते कुछ वर्षों से हरियाणा सरकार ने ड्राइविंग प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैं। इनमें तीन माह की ट्रेनिंग के बदले अच्छी-खासी फ़ीस तो वसूली जाती है परन्तु वास्तविक ट्रेनिंग न के बराबर ही होती है। इसलिये यहां दाखिला लेने वाले दाखिले की सरकारी फ़ीस के साथ-साथ केन्द्र में न आने के बावजूद प्रमाणपत्र पाने की रिश्वत अलग से देते हैं।

इसके हैवी लाइसेंस जारी करने के लिये आरटीए दफ़्तर में सरकारी फ़ीस के अलावा 5000 रु. का चढावा अलग से चढता है। इसी तरह नवीकरण के वक्त भी ऐसा ही कुछ होता है। इतनी मोटी रिश्वत के चलते पिछले दिनों पलवल में फ़र्जी लाइसेंस का एक बड़ा घोटाला सामने आया था। यहां पर यह नहीं कहा जा सकता कि इस धंधे से होने वाली करोड़ों की लूट-कमाई कोई एक अफ़सर अकेला कर रहा है। यह सारा खेल बड़ा ही व्यवस्थित तरीके से दलालों के माध्यम से चलता है और नीचे से लेकर ऊपर तक हर अधिकारी इस दफ़्तर में तैनाती कराने वाले राजनेता तक पहुंचता है। फ़िर चाहे एचसीएस को यहां बैठा लो या एडीसी को या डीएसपी को, लूट का खेल तो बदस्तूर चलता ही रहेगा। जनता को अपनी ईमानदार छवि दिखाने के लिये विजिलेंस व फ्लाईंग स्क्वायड के छापे भी चलते रहेंगे। इसी संदर्भ में स्थानीय विधायक एवं परिवहन मंत्री के उन छापेमारी अभियानों को भी देखा जा सकता है जिनके द्वारा वे अवैध बसों को पकड़ने का नाटक करते थे। इसी तरह वे ओवरलोड डम्परों की पकड़-धकड़ करने का खेल भी खेलते रहे हैं।

कहने की जरूरत नहीं कि लूट का यह पैसा जो सीधे तौर पर ट्रांस्पोर्टरों एवं व्यापारियों से वसूला जाता है वह अंतत: उपभोक्ता की जेब से ही निकलता है।

गतांक की चीर-फ़ाड़

सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ़ तेजी से नीचे गिरा

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

मज़दूर मोर्चा के 7-13 मार्च 2021 के अंक में समसामयिक ज्वलंत मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार व लेख प्रकाशित हुए हैं। नगर निगम फ़रीदाबाद के सदन में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 2593 करोड़ रुपए के घाटे का बजट तो पास हो गया, लेकिन नगर की मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, पानी, सीवर, साफ़-सफ़ाई आदि पर कोई विशेष चर्चा नहीं की गई। 'कैसा विकास: फ़रीदाबाद (नरक) निगम के बजट का 80 फ़ीसदी अफ़सरों -कर्मचारियों पर खर्च होगा-एमसीएफ़ कमिश्नर का कोई विजन बजट में नज़र नहीं आया, शहर में सड़क, पानी, सीवर, सफ़ाई जेसी मूलभूत सुविधाओं पर कोई बात नहीं' में एमसीएफ़ के तथाकथित विकास के लिये बजट की हकीकत का सटीक विश्लेषण किया गया है।

इस बजट में साफ़-सफ़ाई, हरियाली व पर्यावरण तथा सीवर व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिये प्रवधान गायब हैं। प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लिये राशि पिछले साल जितनी ही रखी गई है, जबकि एक सर्वे के मुताबिक प्रॉपर्टी की संख्या नगर में लगभग दुगुना हो गई है। ऐसे में ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का प्रावधान होना चाहिए था। शहर में पानी का संकट है और रेनीवेल व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। जबकि पार्षदों को अपने वार्ड में दो करोड़ रुपए के विकास कार्य कराने की पावर देकर उन्हें खुश किया गया है।

हिन्दुत्व की प्रयोगशाला गुजरात की तर्ज पर यूपी में भी दलित, महिलाओं ओर मुसलमानों के विरुद्ध अपराधों की शिकायत पुलिस द्वारा पूरी तरह से दर्ज नहीं की जाती और आंकड़ों के हेराफ़ेरी से कागजों पर बेहतर अपराध नियंत्रण दिखाया जाता है। पुलिस का राजनीतिकरण व साम्प्रदायिकरण हो चुका है।

दरअसल आरएसएस व भाजपा योगी जैसे प्रचारकों के जरिए जयश्रीराम के नारे लगवा कर तथा योगीजी की तथाकथित 'रामराज्य' वाली छवि की आड़ में तीखा धार्मिक ध्रुवीकरण करने की चुनावी रणनीति पर कार्य कर रहे हैं।

वास्तव में भाजपा व आरएसएस के लोगों का दोहरा मापदंड है। वे मोदीजी की माता के लिये अपशब्द बोलने की विवादास्पद घटना से तो क्रोधित हैं, लेकिन मोदी सरकार की नीतियों व फ़ैसलों की विरोधी महिलाओं के लिये अपशब्दों का प्रयोग करने से कोई गुरेज नहीं करते और उन्हें उनके दर्द का कोई एहसास नहीं होता। वे भूल जाते हैं कि वे महिलाएं भी किसी की मां, दादी हैं।

इस समय जब मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ़ कई महीनों से देशव्यापी किसान आन्दोलन चल रहा है, तब ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन द्वारा 1906 में लाए गए किसान विरोधी तीन कानूनों के खिलाफ़ 1907 में स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अजीत सिंह की अगुवाई में किए गए किसान आंदोलन व अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध उनके क्रांतिकारी जीवन तथा संघर्ष से 'कहां अजीत सिंह और कहां हेडगेवार' में पाठकों को अवगत कराया गया है।

गोरतलब है कि ब्रिटिश उपनिवेशिक सत्ता ने किसानों की एकता व संघर्ष के दबाव में 9 माह बाद तीनों कानून वापिस ले लिए थे, लेकिन अजीत सिंह को गिरफ़्तार करके मांडले जेल भेज दिया था। लेकिन अब ब्रिटिश उपनिवेशिक सरकार की तरह मोदी सरकार किसान आन्दोलन के नेताओं व उनके समर्थकों को आतंकवादी और देशद्रोही करार देकर जेलों में डाल रही है और उनके धरना स्थलों को कंक्रीट व सीमेंट की बैरीकेडिंग से घेर रखा है और उन्हें बुनियादी सुविधाओं व मानवाधिकारों से वंचित कर रखा है। अजीत सिंह का किसान संघर्ष व उनका क्रांतिकारी जीवन उनके लिए प्रेरणा-स्त्रोत साबित है।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हालिया आंकड़ों के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश (यूपी)में बलात्कार, डकैती, हत्या जेसे अपराधों की संख्या में बढोत्तरी हुई है, जबकि स्टार प्रचारक योगी जी पश्चिमी बंगाल के मालदा की चुनावी सभा में यूपी में अपराधियों को गले में जान बख्शने की तख्ती लटकाने के लिये मजबूर करने का दावा कर रहे हैं। 'योगी जी! तख्ती पर सुरक्षा नहीं अराजकता लिखा है' तथा 'यूपी में जंगलराज की ये तस्वीर आपने देखी ?' में हाथरस व गोरखपुर में लड़कियों की यौन प्रताड़ना के अपराधों की खबर, छेड़छाड़, हत्या आदि के संदर्भ में योगी जी के झूठे दावों को बेनकाब किया गया है।

सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ़ तेजी से नीचे गिरने से चिंतित मोदी जी के प्रचारतंत्र ने बीबीसी रेडियो के एक कार्यक्रम में मोदीजी की माता के लिये अपशब्द बोलने की विवादास्पद क्लिपिंग बाहर आते ही सोशल मीडिया पर फ़ौरन इसे भावनात्मक मुद्दा बनाते हुए मोर्चा संभाल लिया और मोदी जी के प्रति हमदर्दी की लहर चल पड़ी। 'सिर्फ मोदी की मां ही मां है, बाकी लोगों की मां फ़िर क्या है' में भाजपा की आईटी सेल द्वारा सोशल मीडिया पर मोदीजी की छवि व लोकप्रियता बढाने की रणनीति का खुलासा किया गया है।